अरुण बी. सहर्या, सी. जे. और वी.के. बाली, जे के समक्ष

हरियाणा राज्य लघु सिंचाई नलकूप

निगम और अन्य - अपीलकर्ता

बनाम

जी.एस. उप्पल और अन्य- उत्तरदाता

L.P.A. 1993 की संख्या 725

22 अगस्त 2001

भारत का संविधान, *1950*- अनुच्छेद *14* और *226*-निगम के सेवा उपनियम-*Rl. 5.1*, भाग *V* -निगम के कर्मचारियों को हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के समान वेतनमान मिलता है-सेवा उपनियमों में प्रावधान है कि निगम के वेतनमान, बोर्ड द्वारा संशोधन के अधीन हैं जो आम तौर पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपनाए गए पैटर्न का पालन करेंगे-निदेशक मंडल सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान के बराबर सभी श्रेणियों के वेतनमानों में संशोधन की सिफारिश करता है- सरकार सभी श्रेणियों के वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दे रही है, लेकिन याचिकाकर्ताओं की केवल तीन श्रेणियों में कटौती कर रही है–

निगम के कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारित करने की शक्ति निगम

के निदेशकों के पास है-निगम केवल याचिकाकर्ताओं की सीमित श्रेणियों के संबंध में वित्तीय बाधाओं का अनुरोध नहीं कर सकता है-निदेशक मंडल के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का सरकार का निर्णय अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है और अविभाज्य भेदभाव की बू आती है-याचिकाकर्ता राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर संशोधित वेतनमान के हकदार हैं।

अभिनिर्धारित किया गया कि यह केवल याचिकाकर्ताओं की श्रेणी है जिसे अलग किया गया है, जबकि अन्य सभी कर्मचारियों, यहां तक कि अपीलार्थी निगम के कर्मचारियों को उनके वेतनमान में वृद्धि दी गई है, जैसा कि उनके समकक्षों i.e. सरकारी विभाग में समान पदों पर, के अनुरूप है। इतना ही नहीं, उक्त वृद्धि अन्य अभियंताओं द्वारा धारण किए गए पदों को दी गई है, यहां तक कि उन पदों को भी, जो याचिकाकर्ताओं के रैंक से ऊपर इंजीनियरिंग पदों पर हैं, उन्हें भी समान वेतन वृद्धि दी गई है। याचिकाकर्ताओं की केवल तीन श्रेणियां हैं, जिन्हें छोड़ दिया गया है। इसके लिए कोई औचित्य नहीं है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जो निगम के अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि को उचित ठहरा सके, जिसमें वे भी शामिल हैं, जो इंजीनियरिंग पदों पर हैं और याचिकाकर्ता नहीं हैं। इस प्रकार, निदेशक मंडल के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के

सरकार के निर्णय से व्यक्तिगत भेदभाव की गंध आती है और यह सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत आता है।

(पैरा 20)

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14, 39 (डी) और 226 - समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत -सरकारी विभागों के इंजीनियरों के वेतनमान में संशोधन- सरकार निगम के इंजीनियरों के वेतनमान में वृद्धि करने से इनकार कर रही है-कर्मचारियों के दो समूह-विभिन्न प्रबंधन और विभिन्न प्रतिष्ठान -निगम और सरकारी विभागों के इंजीनियरों के पदों के बीच कोई समीकरण नहीं -यह दिखाने के लिए कोई आंकड़ा नहीं है कि सरकारी विभागों के इंजीनियरों का काम और कर्तव्य निगम के इंजीनियरों के समान हैं -एक समय में सरकारी विभागों और निगम के पदों पर समान वेतनमान और एक में वृद्धि के कारण अन्य पदों पर समान वेतनमान की वृद्धि होना 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को आकर्षित करने का कोई आधार नहीं है।

अभिनिर्धारित किया गया कि यदि दो पदों को समान किया जाता है और समय-समय पर पारित नियमों या आदेशों से एक समीकरण बनाया जाता है या उस मामले के लिए यदि यह स्थापित किया

जाता है कि कर्मचारियों के दो समूह एक ही काम कर रहे हैं और समान जिम्मेदारियां रखते हैं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (d) में निहित सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को लागू करने के लिए केवल दो न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त आधार हैं। मान लीजिए, तब से याचिकाकर्ताओं द्वारा धारण किए गए पदों को सरकारी विभागों की तीन शाखाओं के इंजीनियरों द्वारा धारण किए गए पदों के बराबर नहीं माना गया है। संक्रमित, याचिकाकर्ताओं का मामला ऐसा भी नहीं है कि कुछ आदेशों के आधार पर इन पदों को तब से समान कर दिया गया है। यह निगम का सकारात्मक मामला है और वास्तव में याचिकाकर्ताओं ने समान काम और समान जिम्मेदारियों का मामला बनाने के लिए सरकारी विभागों की तीन शाखाओं के इंजीनियरों के साथ तुलना करने के लिए अपने काम और कर्तव्यों का कोई विवरण नहीं लाया है। केवल यह तथ्य कि एक समय में दो अलग-अलग विभागों के पदों में समान वेतनमान और एक में वृद्धि ने अन्य में समान वेतनमान में समान वृद्धि को आकर्षित किया, "समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत" को आकर्षित करने का कोई आधार नहीं है। ऐसे मामलों की कमी नहीं है जहां कर्तव्य और दायित्व एक समय में समान हो

सकते हैं लेकिन बाद में बदल सकते हैं। इसके अलावा किसी मामले में सरकार अपने दम पर कर्मचारियों के एक समूह के वेतनमान को कर्मचारियों के दूसरे समूह की वृद्धि के अनुरूप बढ़ा सकती है, लेकिन यह किसी भी मामले में सरकार का विवेकाधिकार है और किसी नागरिक को ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

(पैरा 18)

निपिन मित्तल अधिवक्ता

सूर्यकांत AG (Hy), C.R दहिया DAG (Hy) के साथ, अपीलार्थी के लिए

विवेक भंडारी, उत्तरदाता के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

वी.के. बाली, जे

1. इस सामान्य आदेश के द्वारा, हम 1993 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 725 (H.S.M.I.T.C बनाम जीएस उप्पल) के साथ-साथ 1994 की संख्या 5946 (चक्रवर्ती गर्ग बनाम हरियाणा राज्य) और 1996 के 834 (ए.एस. धीर बनाम हरियाणा राज्य) से जुड़ी दो सिविल रिट याचिकाओं पर निर्णय लेने का प्रस्ताव करते हैं

क्योंकि इन सभी याचिकाओं में कानून और तथ्य के साझे प्रश्न शामिल हैं । ऊपर उल्लिखित सिविल रिट याचिकाओं को 1993 के LPA नंबर 725 के साथ सुनने का आदेश दिया गया था। पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील भी इस बात पर सहमत हैं कि इन सभी मामलों को एक साझे निर्णय द्वारा निपटाए जाने की आवश्यकता है। तथ्यों को मुख्य रूप से 1993 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 725 से उठाया गया है, लेकिन कुछ बाद की घटनाओं का भी उल्लेख किया जाएगा, जिनका उल्लेख केवल बाद में दायर की गई सिविल रिट याचिकाओं में किया जा सकता है।

2. 1993 के LPA नंबर 725 में प्रतिवादी हरियाणा राज्य लघु सिंचाई ट्यूबवेल निगम (इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित) के कर्मचारी हैं और जिस समय याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका दायर की गई, वे निगम में उप-विभागीय अधिकारी, उप-विभागीय अभियंता और सहायक अभियंता के पदों पर काम कर रहे थे, जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है। यह उत्तरदाताओं (बाद में याचिकाकर्ताओं के रूप में संदर्भित) का मामला रहा है कि हरियाणा राज्य निगम पर गहरा और व्यापक नियंत्रण रखता है । हरियाणा के राज्यपाल ; सचिव, हरियाणा

सरकार, सिंचाई विभाग; सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग; अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड; सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग; और मुख्य अभियंता (नहरें), सिंचाई कार्य, हरियाणा, वर्ष 1970 में इसके गठन के समय निगम में विशेष शेयरधारक थे। निगम को वर्ष 1970 में हरियाणा राज्य में सिंचाई और बिजली मंत्रालय में से अलग किया गया था । चूंकि, निगम को सिंचाई विभाग से अलग किया गया था, इसलिए शुरुआत में उप-विभागीय अधिकारियों, उप-विभागीय इंजीनियरों और सहायक अभियंताओं के पदों पर काम करने के लिए सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। वर्ष 1992 में जब याचिका दाखिल हुई, उस समय सिंचाई विभाग से 27 SDO प्रतिनियुक्ति पर थे। निगम में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त पदाधिकारियों एवं SDO के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की प्रकृति एक समान थी। उनके कर्तव्य परस्पर-परिवर्तनीय थे और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं का मामला यह रहा है कि एक प्रतिनियुक्ति अधिकारी और निगम के एक एसडीओ द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बीच कोई अंतर नहीं था। दरअसल, याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़कें),

सार्वजनिक स्वास्थ्य और विभिन्न बोर्ड और निगम, जैसे कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, आदि, में SDO, SDE और AE के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है । निगम के सेवा उपनियमों के भाग V के नियम 5.1 इस प्रकार है: -

"(1) निगम में प्रत्येक पद के लिए एक समय वेतनमान होगा; वर्तमान वेतनमान परिशिष्ट II में दर्शाया जा रहा है।

(2) वेतनमान बोर्ड द्वारा संशोधन के अधीन है, जो, हालांकि, आम तौर पर समय-समय पर हरियाणा सरकार द्वारा अपनाए गए पैटर्न का पालन करेगा।"

3. वर्ष 1970 में अपनी स्थापना के बाद से ही, निगम अपने सभी वर्गों के कर्मचारियों के संबंध में समय-समय पर संशोधित हरियाणा सरकार द्वारा अपनाए गए वेतनमान का पालन कर रहा है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, शुरू में, जब निगम का गठन हुआ था, तो मुख्य अभियंता से लेकर सहायक अभियंता/उपमंडल अधिकारी के पद तक के लगभग पूरे इंजीनियरिंग स्टाफ को सिंचाई विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था, जब तक कि निगम ने सहायक अभियंताओं

के संवर्ग की अपनी भर्ती नहीं की। सहायक अभियंता, उपमंडल अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के पद पर भर्ती और पदोन्नति के लिए योग्यताएं और अनुभव सिंचाई विभाग के समान ही हैं। वे सभी, जो किसी भी पद पर प्रतिनियुक्ति पर आए थे, उन्हें पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक स्वास्थ्य (बी एंड आर) और सिंचाई विभाग जैसे सरकारी विभागों में इंजीनियरों के लिए समय-समय पर हरियाणा सरकार द्वारा संशोधित वेतनमान दिया गया था। इन तथ्यों और समान काम के लिए समान वेतन के स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इंजीनियरों सहित निगम के कर्मचारियों के वेतनमान को 1 अप्रैल, 1979 और 1 जनवरी, 1986 से हरियाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए स्वीकृत वेतनमान वेतन संशोधन के पैटर्न पर संशोधित किया गया था। 1 जनवरी, 1986 से वेतनमान में संशोधन को हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/ बोर्डों/ निगमों के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए गठित वेतन संशोधन समिति ने दिनांक 21 सितंबर, 1988 को अपनी बैठक में भी मंजूरी दे दी थी। निगम के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खंड 81(v) के आधार पर, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है, याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि

निगम के बोर्ड के पास अपने विवेक से निगम के कर्मचारियों की वेतन और परिलब्धियां तय करने की अंतिम शक्ति है।:-

“81(v) स्थायी, अस्थायी या विशेष सेवाओं के लिए ऐसे प्रबंधकों, सचिवों, अधिकारियों, क्लर्कों, एजेंटों और सेवकों को अपने विवेक से नियुक्त करना, हटाना या निलंबित करना, जैसा कि वे समय-समय पर उचित समझें, और उनकी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करें और उनके वेतन या परिलब्धियों को तय करने और ऐसी राशि की सुरक्षा की मांग करने के लिए जो वे ऐसे मामलों में उचित समझते हैं। पहले, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को उपलब्धता के आधार पर सिंचाई विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा।“

4. निगम के अध्यक्ष की शक्ति से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खंड 95 के आधार पर, याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला रहा है कि यदि अध्यक्ष सरकार को कोई प्रस्ताव भेजता है और निर्णय के संबंध में सरकार के विचार दो महीने की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होने पर, निदेशक सरकार को आगे संदर्भ दिए बिना प्रस्ताव या निर्णय के अनुसार कार्य करने का हकदार होगा।

5. 1 जनवरी, 1986 से निगम में इंजीनियरों के लिए संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद, हरियाणा सरकार ने अधीक्षण अभियंताओं के वेतनमान में कुछ विसंगतियों को दूर करते हुए, पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक स्वास्थ्य (भवन और सड़कें) और सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंताओं के वेतनमान को 3700-5000 रुपये से रु. 4100-5300 –वित्त विभाग के पत्र संख्या 6\38\3पीआर (एफडी)–27 दिनांक 16 मई, 1989 के माध्यम से और संशोधित किया और –उक्त विभाग के एक अन्य पत्र संख्या 6\38\पीआर दिनांक 2 जून, 1989 के माध्यम से, अन्य इंजीनियरों जैसे AEE\SDO\SDE (क्लास-I और क्लास-II) के वेतन को भी 1 मई, 1989 से संशोधित किया गया था। निगम के निदेशक मंडल ने 18 अगस्त, 1989 को आयोजित अपनी 94वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि निगम कर्मचारियों और हरियाणा सरकार के विभागों में उनके समकक्षों के बीच पूर्व में बनाए गए वेतनमान में समानता को ध्यान में रखते हुए, जिसे वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था, वित्त विभाग, हरियाणा, के सार्वजनिक उद्यम और निवेश कक्ष को उनकी सहमति के लिए अनुशंसित किया जा सकता है:-

पोस्ट का नाम	मौजूदा वेतनमान	संशोधित वेतनमान
अधीक्षण अभियंता	रुपये. 3700-5000	रुपये. 4100-5300
इंजीनियर्स	रुपये. 2200 -4000	रुपये. 2200 -4000
एईई / एई / एसडीओ	रुपये. 2000-3500	रुपये. 3000- 4500
एसडीई (कक्षा 1 और II)		(5 वर्षों के नियमित सेवा के बाद) रुपये. 4100-5300 (12 साल के नियमित सेवा के बाद).

6. हरियाणा सरकार ने 16 मई, 1990 के पत्र के माध्यम से इंजीनियरों के वेतनमान में एक बार फिर संशोधन किया, जो 1 मई, 1989 से निम्नानुसार प्रभावी होगा:-

पद का नाम	मौजूदा वेतनमान	संशोधित वेतनमान
इंजीनियर AEE/AE/SDO/SDE	रु. 2200-4000 रु. 3000-4500 (5 वर्ष की	रु. 2200-4000 रु. 3000-4500 (5 वर्ष की नियमित

	नियमित सेवा के बाद)	संतोषजनक सेवा के बाद)
	रु. 4100-5300 (12 वर्ष की नियमित सेवा के बाद)	चयन ग्रेड रु. 4100-5300 (12 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के बाद) 20% के कैडर पदों तक सीमित

7. निगम के निदेशक मंडल ने 25 जून, 1990 को आयोजित अपनी 97वीं बैठक में निगम के इंजीनियरों के संबंध में 1 मई, 1989 से उपरोक्त संशोधित वेतनमानों को अपनाने पर विचार किया और मंजूरी दी, बशर्ते वित्त विभाग की सहमति हो । आगे यह निर्णय लिया गया कि इंजीनियरों के वेतनमान में हरियाणा सरकार द्वारा किया गया कोई भी संशोधन वित्त विभाग की सहमति के अधीन, निगम कर्मचारियों के संबंध में भी लागू किया जा सकता

है। निगम इंजीनियरों के वेतनमान में संशोधन के लिए निगम के निदेशक मंडल का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था और उक्त प्रस्ताव में स्थायी समिति के ध्यान में लाया गया था कि संशोधित वेतनमान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों के लिए पहले ही प्रदान किया जा चुका है और हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने भी अपने इंजीनियरों के वेतनमान में संशोधन किया है। उपरोक्त प्रस्ताव 28 मई, 1992 को हुई बैठक में स्थायी समिति के समक्ष आया, जिसने चयनात्मक तरीके से वेतनमान को मंजूरी दी। अधीक्षण अभियंताओं, लेखा अधिकारियों, सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन, डिवीजनल हेड ड्राफ्ट्समैन आदि के वेतनमानों में संशोधन को मंजूरी दी गई, जबकि याचिकाकर्ताओं, जो एई/एसडीओ/ एसडीई हैं, के वेतनमानों में संशोधन को स्थगित कर दिया गया था और निर्णय लिया गया कि इस मामले की जांच वित्त विभाग द्वारा अलग से की जाएगी। हालांकि, जहां तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, वेतनमान में संशोधन के संबंध में मामला स्थायी समिति द्वारा नहीं उठाया गया था, इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को बार-बार अभ्यावेदन दाखिल करने के लिए बाध्य किया गया और जब इसका कोई परिणाम नहीं निकला, तो वर्तमान याचिका दायर की गई।

8. याचिकाकर्ताओं के तर्क का प्रतिवादियों ने विरोध किया, जिसमें यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता पीडब्ल्यूडी के तीन विंगों के इंजीनियरों की तर्ज पर संशोधित वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए 15 नवंबर, 1991 को आयोजित बैठक में स्थायी समिति के विचार के लिए निगम का प्रस्ताव रखा गया था। उपरोक्त बैठक में लिया गया निर्णय इस प्रकार है: -

"एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया जिसमें सदस्य सचिव, हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज; प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई ट्यूबवेल निगम और संयुक्त सचिव वित्त (वेतन संशोधन) H.S.M.I.T.C के वेतनमान के साथ-साथ पूरे स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करेंगे। उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर, यदि आवश्यकता हो तो निगम स्थायी समिति के विचार के लिए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

9. उप-समिति की उपरोक्त बैठकें 16 जनवरी, 1992 और 6 फरवरी, 1992 को आयोजित की गईं। उप-समिति की सिफारिशों वाली इन बैठकों के कार्यवृत्त को 28 मई 1992 को आयोजित बैठक में

स्थायी समिति के विचार के लिए रखा गया था जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

"एईई\एई\एसडीओ\एसडीई के पदों के वेतनमान में संशोधन को स्थगित कर दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि इस मामले की वित्त विभाग द्वारा अलग से जांच की जाएगी।"

10. आगे यह दलील दी गई है कि चूंकि मामला सक्रिय विचाराधीन था और अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं था और इसलिए, रिट याचिका समय से पहले होने के कारण खारिज की जा सकती थी। इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि बाद के चरण में, यानी 6 मार्च, 1992 को, सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया था, जिसकी एक प्रति हमें बहस के दौरान सौंपी गई थी। वह इस प्रकार है:-

“मुझे हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के परिपत्र पत्र संख्या 6\38\3पीआर (एफडी)-87 दिनांक 2 जून, 1989 और क्रमांक 6\38\पीआर (एफडी)-87 दिनांक 16 मई 1990 का संदर्भ आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है- जिसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षकों के साथ इंजीनियरों के वेतनमान को और संशोधित किया गया। यह

स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक इंजीनियरों का सवाल है, संशोधित वेतनमान केवल पीडब्ल्यूडी (तीन विंग) के इंजीनियरों पर लागू है।"

11. उत्तरदाताओं का यह भी मामला रहा है कि H.S.M.I.T.C. और पीडब्ल्यूडी के तीन विंगों के इंजीनियरों के कर्तव्यों, विश्वसनीयता और जिम्मेदारियों के बीच स्पष्ट अंतर था। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को राज्य द्वारा अपने चरणबद्ध कार्यक्रमों और समयबद्ध कार्यक्रम के तहत विकास गतिविधियों के कारण विभिन्न परिस्थितियों और बाधाओं के तहत काम करना पड़ता है। जवाब दावा में दोहरा बचाव पेश किया गया है, जैसा कि जवाब दावा को पढ़ने से स्पष्ट है, कि पीडब्ल्यूडी के केवल तीन विंगों के इंजीनियरों के वेतनमान में संशोधन हुआ है और राज्य सरकार के विभागों में कार्यरत इंजीनियरों को उन कर्तव्यों को पूरा करना होगा जो निगम के इंजीनियरों द्वारा किए गए कर्तव्यों से कहीं अधिक कठिन हैं, जहां याचिकाकर्ता कार्यरत हैं। यह तथ्य कि निगम, जहां याचिकाकर्ता कार्यरत हैं, घाटे में चल रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत दायर की गई सिविल विविध संख्या 2547/2001 में की गई दलीलों के आधार पर बहस के दौरान भी उठाया गया है और यह आग्रह

किया गया है कि अपनी वित्तीय स्थिति के कारण, निगम याचिकाकर्ताओं के वेतनमान को सरकार के तीनों विभागों के इंजीनियरों के वेतनमान के बराबर करने की स्थिति में नहीं है।

12. जब मामला विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आया, तो याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया कि प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे लोगों से अलग व्यवहार करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई भेदभावपूर्ण थी और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है । प्रतिनियुक्ति पर आए लोगों और उन लोगों को, जो मूल रूप से निगम में कार्यरत थे, एक समान मानते हुए, उनके कर्तव्य परस्पर/परिवर्तनशील हैं और कर्मचारियों के दोनों समूहों द्वारा किए जा रहे कर्तव्य भी समान हैं, यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं और ऐसे एसडीओ जिनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की गई थी, के बीच कोई वैध वर्गीकरण नहीं था। आगे यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने 1 जनवरी 1986 से 2000-3500 रुपये के वेतनमान में काम करना जारी रखा है और सरकार में उनके समकक्ष और वे व्यक्ति भी, जो प्रतिनियुक्ति के माध्यम से निगम में तैनात थे, के बीच किसी भी वर्गीकरण के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं था। निगम को हुए नुकसान पर आधारित तर्क को इस आधार

पर खारिज कर दिया गया कि निगम ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए ट्यूबवेल खोद रहा था और जल प्रवाह/चैनलों की लाइनिंग का कार्य कर रहा था, जिसकी लागत भूमि मालिकों द्वारा भुगतान की जानी थी और चुनाव के समय, किसानों की देय राशि माफ कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप निगम अपनी वास्तविक लागत भी वसूल करने में असमर्थ रहा। निगम को हुए नुकसान का कारण होने के कारण इस तर्क को नजरअंदाज कर दिया गया।

13. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह भी माना गया कि घटनाओं का क्रम स्पष्ट रूप से दर्शाएगा कि निगम के कर्मचारियों के साथ हर अवसर पर वेतनमान के संशोधन के समय सरकार के कर्मचारियों के बराबर व्यवहार किया गया था और यह स्थिति को स्वीकार किया गया था यह है कि वेतनमानों को शुरू में 1 अप्रैल, 1979 से और उसके बाद 1 जनवरी, 1986 को संशोधित किया गया था और इन दोनों अवसरों पर, निगम के कर्मचारियों के वेतनमान सरकारी कर्मचारियों के बराबर थे और इसके अलावा ऐसा कुछ भी ऐसा हुआ दिखाई नहीं देता है जो विभेदक उपचार को उचित ठहरा सकता है।

14. श्री सूर्य कांत शर्मा, विद्वान महाधिवक्ता, जो अपीलकर्ता - हरियाणा राज्य की ओर से पेश हुए, ने जोरदार तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के कर्तव्यों की तुलना सरकारी विभागों के तीन विंगों के इंजीनियरों से नहीं की जा सकती, जब वे अपीलकर्ता निगम के साथ प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे थे । मामलों के स्थापित तथ्यों से पता चलता है कि अपीलकर्ता निगम को सौंपे गए कार्य पहले सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा किए जाते थे और जब निगम अस्तित्व में आया, तो इसे उन कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाना था, चीजों के स्वभाव से ही जिनको शुरू में सरकार के सिंचाई विभाग से ही प्रतिनियुक्ति पर लाना पड़ा। विद्वान महाधिवक्ता का तर्क है कि जब भी अपीलकर्ता निगम ने नई नियुक्तियाँ करना शुरू किया, प्रतिनियुक्ति, यह फिर से एक स्वीकृत स्थिति है, को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया। प्रतिनियुक्ति पर और स्वाभाविक रूप से सीमित अवधि के लिए, यदि सरकारी विभागों के कर्मचारी वही कर्तव्य निभा रहे थे जो निगम के मूल कर्मचारी कर रहे थे, तो यह नहीं माना जा सकता कि उनका काम समान था ताकि 'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत आकर्षित किया जा सके। विद्वान वकील द्वारा यह भी आग्रह किया गया है कि केवल यह

तथ्य कि पिछले दो मौकों पर सरकारी विभागों के इंजीनियरों के वेतन में बढ़ोतरी के कारण अपीलकर्ता निगम में कार्यरत इंजीनियरों के वेतन में एक समान वृद्धि हुई थी, कोई मार्गदर्शिका नहीं है जो निर्णायक रूप से यह दिखा सकती है कि कर्मचारियों के दो समूह की प्रकृति और कर्तव्य समान थे। ऐसा होने पर, सरकारी विभागों के वेतनमानों में वृद्धि से बाद के सभी अवसरों पर अपीलकर्ता निगम के इंजीनियरों के वेतनमानों में समान वृद्धि नहीं हो सकेगी। हमारे सामने यह भी तर्क दिया गया है कि न्यायालय के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई डेटा नहीं था कि सरकारी विभागों में कार्यरत इंजीनियर समान कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और उनकी जिम्मेदारियाँ भी उतनी ही थीं जितनी कि अपीलकर्ता निगम में कार्यरत इंजीनियरों की थीं तब भी जब सरकारी विभागों में कार्यरत इंजीनियर निगम में प्रतिनियुक्ति पर नहीं थे । विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्ताओं को दी गई राहत से इनकार करने के लिए बहस के दौरान अपीलकर्ता निगम की कमजोर वित्तीय स्थिति को भी सेवा में लाया जा रहा है।

15. विद्वान वकील के ऊपर उल्लिखित तर्क में काफी योग्यता प्रतीत होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल

न्यायाधीश का निर्णय "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत पर या उस मामले के लिए, कर्मचारियों के समान समूहों के बीच भेदभाव पर आधारित है, को संभवतः बरकरार नहीं रखा जा सकता है, भले ही अन्य बिंदुओं पर, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से हमारे सामने आग्रह किया गया है, जिसे हम फैसले के बाद के भाग में संदर्भित करेंगे, अंतिम परिणाम वही हो ।

16. इससे पहले कि हम कर्मचारियों के दो समूहों द्वारा किए जा रहे समान या बराबर कार्य के संबंध में तथ्यों पर वापस आएं, हम कर्मचारियों के दो समूहों के अलग-अलग प्रबंधन और अलग-अलग प्रतिष्ठानों के तहत होने वाले प्रभाव से निपटना चाहेंगे। यह अब तक कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जिस भेदभाव की शिकायत की गई है वह समान प्रबंधन की एक ही स्थापना के साथ होना चाहिए, क्योंकि कानून का सिद्धांत, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, फिर से एकीकृत नहीं है, हम सीधे हरबंस लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य[1] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसलों का जिक्र करते हुए रणधीर सिंह बनाम भारत संघ[2], उत्तर प्रदेश राज्य बनाम

---

[1] 1989 (2) RSJ 509

[2] 1982 (1) SCC 618

जे.पी. चौरसिया[3], एवं मेवा राम कनौजिया बनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान[4] और साथ ही अखिल भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आशुलिपिक (मान्यता प्राप्त) बनाम भारत संघ[5] में यह माना गया था कि "अलग-अलग प्रबंधन वाले अन्य प्रतिष्ठानों में समकक्षों के साथ, या यहां तक कि एक ही मास्टर के स्वामित्व में होने के बावजूद विभिन्न भौगोलिक स्थानों में प्रतिष्ठानों में भी समानता नहीं बनाई जा सकती है। जब तक यह नहीं दिखाया जाता कि एक ही प्रतिष्ठान में एक ही मास्टर द्वारा कर्मचारियों के एक ही समूह के बीच भेदभाव किया जाता है, "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है। दलीलों में यह एक स्वीकृत तथ्य था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निष्कर्ष भी यही था कि निगम के पास कोई नियमित रूप से नियोजित बढ़ई नहीं था और यहां तक कि यह मानते हुए कि याचिकाकर्ताओं की नौकरियां सरकारी सेवा में उनके समकक्षों के साथ तुलनीय थीं, यह माना गया कि याचिकाकर्ता "समान काम के लिए समान वेतन" का अधिकार लागू नहीं कर सकते।

[3] 1989 (1) SCC 121
[4] 1989 (2) SCC 235
[5] 1988 (3) SCC 91

17. "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धांत यह माना जाता है कि यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है जिसकी स्पष्ट रूप से गारंटी दी गई हो, भले ही यह समान रूप से निर्विवाद रहा है कि उपरोक्त सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (डी) के तहत शामिल किया गया है। इस सत्य में कोई संदेह नहीं है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन बाद के यूपी राज्य बनाम जेपी चौरसिया और मेवा राम कनौजिया बनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के फैसले में यह माना गया कि "समान कार्य के लिए समान वेतन" का सिद्धांत समान कार्य के प्रत्येक मामले में यांत्रिक अनुप्रयोग नहीं है और यह भी कि उपरोक्त सिद्धांत को विशेष रूप से पेशेवर सेवाओं के क्षेत्र में हर प्रकार की सेवा में लागू नहीं किया जा सकता है।

18. मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह याद किया जा सकता है कि लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग के तीन विंगों में इंजीनियरों, जब केवल अपीलकर्ता निगम के साथ

प्रतिनियुक्ति पर होंगे, उनके पास वही कर्तव्य और जिम्मेदारियां होंगी जो कि निगम के कर्मचारियों की थीं लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ऐसे इंजीनियर, जो सरकारी विभागों से संबंधित हैं, काम कर रहे हैं, भले ही निगम में उन्हीं पदों पर सीमित समय के लिए काम कर रहे हों, क्योंकि उन्हें शुरू में अपीलकर्ता निगम के कार्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाना था। यह घटता हुआ कैडर था जिसे पूरी तरह से समाप्त करना पड़ा जब प्रतिनियुक्ति पर निगम द्वारा ही पद भरे गए। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा परिस्थितियों के बल पर ऐसी सीमित अवधि के लिए समान कार्य किया जाता है, जिसके लिए उन्हें प्रतिनियुक्ति पर रहना होता है और वही कर्तव्य निभाने होते हैं, जो सरकारी विभागों के कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में "समान कार्य के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करता है। स्वाभाविक रूप से, जब ऐसे प्रतिनियुक्तिकर्ताओं को अपने मूल विभाग में वापस जाना था, तो वे कहीं अधिक कठिन कर्तव्यों का पालन कर रहे होंगे, जैसा कि तर्कों के दौरान आग्रह किया गया है। न्यायालय के समक्ष कोई डेटा नहीं था, न ही वास्तव में इसका आग्रह किया गया था, लेकिन आम तौर पर यह कहा गया

था कि सरकारी विभागों के इंजीनियरों के काम और कर्तव्य निगम के इंजीनियरों के समान थे और ऐसा होने पर, कुल मिलाकर, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सरकारी विभागों के इंजीनियर निगम के इंजीनियरों के समान ही कर्तव्य निभा रहे थे और उनकी समान जिम्मेदारियाँ भी थीं । विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया तर्क कि पहले दो अवसरों पर, निगम के इंजीनियरों के वेतनमान में वही वृद्धि हुई थी जो सरकारी विभागों के इंजीनियरों को दी गई थी और इसमें कोई अंतर नहीं दिखाया गया था और इसलिए, याचिकाकर्ताओं को सरकारी विभागों के इंजीनियरों को दिए जाने वाले वेतनमान की तुलना में बढ़ा हुआ वेतनमान मिलेगा, जिसे हम सम्मान के साथ संभवतः बरकरार नहीं रख सकते। उक्त दृष्टिकोण के समर्थन में हमारे सामने किसी भी न्यायिक मिसाल का हवाला नहीं दिया गया है। दूसरी ओर, "समान कार्य के लिए समान वेतन" के सिद्धांत पर न्यायिक उदाहरणों की श्रृंखला यह सुझाव देती है कि केवल तभी जब दो पदों को समान किया जाता है और समय-समय पर पारित नियमों या आदेशों से उस मामले के लिए समीकरण बनाया जाता है, यदि यह स्थापित है कि कर्मचारियों के दो समूह समान कार्य कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारियाँ

समान हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (डी) में निहित सिद्धांत का आह्वान किया जा सकता है। समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने के लिए ये केवल दो न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त आधार हैं", माना जाता है कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं द्वारा धारण किए गए पदों को सरकारी विभागों के तीन विंगों के इंजीनियरों द्वारा धारण किए गए पदों के बराबर नहीं किया गया है। वास्तव में याचिकाकर्ताओं का मामला भी ऐसा नहीं है कि किसी आदेश के आधार पर इन पदों को एक समान कर दिया गया है। यह अपीलकर्ता का सकारात्मक मामला है और वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने समान काम और समान जिम्मेदारियों का मामला बनाने के लिए सरकारी विभागों के तीन विंगों के इंजीनियरों के साथ तुलना करने के लिए अपने काम और कर्तव्यों का कोई विवरण नहीं दिया है। केवल यह तथ्य कि एक ही समय में दो अलग-अलग विभागों में पदों के लिए समान वेतनमान थे और एक में वृद्धि से अन्य में भी वेतनमान में समान वृद्धि हुई, हमारे विचार में, "समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत" को आकर्षित करने का कोई आधार नहीं है। ऐसे मामलों की कमी नहीं है जहां कर्तव्य और जिम्मेदारियां एक समय में

समान हो सकती हैं लेकिन बाद में बदल सकती हैं। इसके अलावा, किसी दिए गए मामले में सरकार, अपने दम पर, कर्मचारियों के एक समूह के वेतनमान को दूसरे समूह के कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि के अनुरूप बढ़ा सकती है, लेकिन यह किसी भी मामले में सरकार का विवेक है और नागरिक को इस तरह का कोई अधिकार नहीं देता है।

19. उपरोक्त स्थिति का सामना करते हुए, लेटर्स पेटेंट अपील के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि विभाग द्वारा बनाए गए सेवा उपनियमों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए और उक्त सेवा उपनियमों के आधार पर, याचिकाकर्ता अपने वेतनमान में वृद्धि के हकदार हैं जो कि सरकारी विभाग के इंजीनियरों को दिया गया है। यह भी आग्रह किया गया है कि उपरोक्त उपनियमों के आधार पर, अपीलकर्ता निगम ने पहले ही निगम के अन्य सभी कर्मचारियों को वेतनमान में समान वृद्धि दे दी है और केवल याचिकाकर्ता, जो इंजीनियर हैं, को एकल कर

दिया गया है, यह भेदभावपूर्ण है और इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

20. हरियाणा राज्य लघु सिंचाई ट्यूबवेल निगम लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। रिट याचिका के पैराग्राफ 6 में यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि सेवा उपनियम निगम द्वारा बनाए गए हैं और सेवा उपनियमों के भाग V के नियम 5.1 के अनुसार, निगम में प्रत्येक पद के लिए एक समय वेतनमान होगा; वर्तमान वेतनमान को परिशिष्ट II में दर्शाया गया है और आगे कहा गया है कि वेतनमान बोर्ड द्वारा संशोधन के अधीन है, जो, हालांकि, आम तौर पर समय-समय पर हरियाणा सरकार द्वारा अपनाए गए पैटर्न का पालन करेगा । उत्तरदाताओं की ओर से दायर जवाब दावा में या बहस के दौरान उपरोक्त नियम के न तो अस्तित्व और न ही प्रयोज्यता पर सवाल उठाया गया है। रिट याचिका के पैराग्राफ 21 (सी) में आगे यह अनुरोध किया गया है कि निगम के कर्मचारियों के वेतनमान बोर्ड द्वारा संशोधन के अधीन हैं, जो, हालांकि, आम तौर पर सरकार द्वारा अपनाए गए पैटर्न का पालन करेंगे और 1970 में इसकी स्थापना के बाद से, निगम के कर्मचारियों को हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के समान

वेतनमान मिल रहा था और निदेशक मंडल ने पहले ही निगम के इंजीनियरों के वेतनमान के बराबर कर दिया था , सरकार इसे अपनाने के लिए बाध्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है, उपरोक्त सेवा उपनियमों के आधार पर, बोर्ड आम तौर पर समय-समय पर हरियाणा सरकार द्वारा अपनाए गए पैटर्न का पालन करेगा, लेकिन इस मामले में, सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान के अनुरूप याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई मांग के अनुसार वेतनमान में वृद्धि की सिफारिश पहले ही की जा चुकी है और यह केवल सरकार है जो निदेशक मंडल के निर्णय से सहमत नहीं है। हमें इस सवाल पर जाने की जरूरत नहीं है कि 'आम तौर पर' शब्द की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए, यानी, क्या इसका मतलब 'निरंतर' होगा और यदि ऐसा नहीं है, तो निगम वेतनमान के समान पैटर्न का पालन न करने के लिए कुछ कारण बताने के लिए बाध्य है, साथ ही, निगम ने वास्तव में सरकारी विभागों के तीन विंगों में समान पद रखने वाले इंजीनियरों के वेतनमान के अनुरूप याचिकाकर्ताओं द्वारा रखे गए पदों की श्रेणियों में वेतनमान में वृद्धि की अनुमति दी है। ऐसा होने पर, एकमात्र प्रश्न यह होगा कि क्या सरकार निगम के उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है । अनुच्छेद 81(v) के आधार पर जैसा कि निगम द्वारा तैयार किया गया है

निगम के निदेशकों को अपने विवेक से ऐसे प्रबंधकों, सचिवों, अधिकारियों, क्लर्कों, एजेंटों और सेवकों को स्थायी, अस्थायी या विशेष सेवाओं के लिए नियुक्त करने, हटाने या निलंबित करने की शक्तियाँ हैं, जैसा कि वे समय-समय पर उचित समझें, और उनकी शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए और उनके वेतन या परिलब्धियाँ तय करने के लिए और ऐसी राशि की सुरक्षा की मांग करें जो वे ऐसे मामलों में उचित समझें। इस प्रकार, कर्मचारियों के लिए वेतन या परिलब्धियाँ तय करने की शक्ति विशेष रूप से कंपनी के निदेशकों के पास है और सेवा उपनियमों के भाग V के नियम 5.1 के आधार पर, जैसा कि निर्णय के पहले भाग में उल्लेख किया गया है, निगम याचिकाकर्ताओं के दावे पर अनुकूल रूप से विचार करते हुए उनके लिए उसी वेतनमान की सिफारिश की गई, जैसा कि सरकारी विभागों की सेवा में उनके समकक्षों को दिया जा रहा है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सरकार द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया है। उपरोक्त आदेश में जो कुछ कहा गया है, वह यह है कि जहां तक इंजीनियरों का सवाल है, संशोधित वेतनमान केवल तीन विंगों पर लागू है। रिट याचिका के पैराग्राफ 14 में यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि वेतनमान में संशोधन के लिए

निगम के निदेशक मंडल का प्रस्ताव 28 मई, 1992 को हुई बैठक में स्थायी समिति के समक्ष आया और स्थायी समिति ने चयनात्मक तरीके से वेतन को मंजूरी दे दी। अधीक्षण अभियंताओं, लेखा अधिकारियों, सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन, डिवीजनल हेड ड्राफ्ट्समैन आदि के वेतनमानों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई, जबकि याचिकाकर्ताओं, जो एई/एसडीओ/एसडीई हैं, के वेतनमानों में संशोधन को स्थगित कर दिया गया और यह निर्णय लिया गया इस मामले की जांच वित्त विभाग द्वारा अलग से की जाएगी। 28 मई, 1992 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति अनुबंध पी-6 के माध्यम से रिकॉर्ड में रखी गई है। उत्तरदाताओं की ओर से दायर जवाब दावे के संबंधित पैरा में जो कुछ कहा गया है, वह यह है कि प्रारंभिक आपत्तियों में किए गए प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर, इस पैरा की सामग्री को स्वीकार किया जाता है। 1996 की सिविल रिट याचिकाकर्ता संख्या 834 में, पैराग्राफ 21(ix) में कहा गया है कि निगम के निदेशक मंडल द्वारा वित्त विभाग की मंजूरी के अधीन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन की सिफारिश की गई थी और उक्त विभाग ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों, जैसे अधीक्षण अभियंता, लेखा अधिकारी, सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन, डिवीजनल हेड

ड्राफ्ट्समैन, जिलेदार आदि के वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दे दी थी और जहां तक एसडीओ/एसडीई/एई का संबंध है, यह स्पष्ट भेदभाव का मामला था । प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से दायर जवाब के संबंधित पैरा में, यह कहा गया है कि "जैसा कि प्रारंभिक आपत्ति और पूर्ववर्ती पैरा में पहले ही बताया गया है, एसडीओ/एसडीई/जेई के संशोधित वेतनमान केवल पीडब्ल्यूडी के 3 विंगों तक ही सीमित थे इसलिए याचिकाकर्ता संशोधित वेतनमान के हकदार नहीं हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं होता है। इसलिए प्रतिवादी की कार्रवाई मनमानी, अवैध और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 39 (डी) का उल्लंघन नहीं है।" ऊपर दी गई पार्टियों की दलीलों से यह पता चलता है कि यह केवल याचिकाकर्ताओं की श्रेणी है, जिसे अलग कर दिया गया है, जबकि अन्य सभी कर्मचारियों, यहां तक कि अपीलकर्ता निगम के भी, को उनके वेतनमान में वृद्धि दी गई है, जैसा कि उनके समकक्षों के अनुरूप है, i.e., सरकारी विभागों में समान पदों पर हैं। इतना ही नहीं, उक्त वृद्धि अन्य इंजीनियरों द्वारा धारण किए गए पदों पर भी दी गई है, यहां तक कि जो लोग याचिकाकर्ताओं के रैंक से ऊपर के इंजीनियरिंग पदों पर हैं, उन्हें भी समान वेतन वृद्धि दी गई

है। याचिकाकर्ताओं की केवल तीन श्रेणियां हैं, जिन्हें छोड़ दिया गया है। क्या इसका कोई औचित्य है, अत: क्या यह एकमात्र प्रश्न है जिसे निर्धारित किया जाना है? हमें जवाब दावे में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं मिला है या जो तर्क के दौरान आग्रह किया गया हो, जो निगम के कर्मचारियों की अन्य सभी श्रेणियों के वेतनमान में वृद्धि को उचित ठहरा सकता है, जिनमें इंजीनियरिंग पद धारण करने वाले लोग भी शामिल हैं, और याचिकाकर्ता नहीं। इस प्रकार निदेशक मंडल के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के सरकार के निर्णय से व्यक्तिगत भेदभाव की बू आती है और यह सीधे तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। बचाव में जो कुछ भी कहा जा सकता है वह एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के अनुच्छेद 135 पर आधारित है , जो इस प्रकार है: -

“135. किसी भी अनुच्छेद में निहित किसी भी बात के बावजूद, सरकार समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जिन्हें वह बोर्ड नीति के मामले में आवश्यक समझे और उसी तरह ऐसे किसी भी निर्देश को अलग कर सकती है और रद्द कर सकती है। कंपनी जारी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करेगी।”

21. सबसे पहले, अनुच्छेद 81(v) के साथ-साथ सेवा उपनियमों के 5.1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अपने कर्मचारियों को वेतनमान देना कोई नीतिगत निर्णय नहीं लगता है जो बोर्ड द्वारा लिया गया हो और यदि ऐसा है भी, तो संभवतः इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को अलग कर दिया गया है, जबकि अन्य सभी कर्मचारियों के संबंध में बोर्ड का वही निर्णय सरकार के साथ स्वीकार या सहमत हो चुका है।

22. जहाँ तक, रिट याचिका में अपीलकर्ता निगम की वित्तीय स्थिति से संबंधित दलीलें और सिविल विविध 2001 की संख्या 3547 में बहस के दौरान दायर की गई शामिल दलीलों का संबंध है, यह कहना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता का मामला यह नहीं है कि यह वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है। यह सच हो सकता है कि वर्तमान में कुछ बैंकों ने 96 करोड़ रुपये की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण में अपीलकर्ता के खिलाफ विभिन्न आवेदन दायर किए होंगे जैसा कि पूर्वोक्त विविध आवेदन में दलील है लेकिन यह निगम का ही मामला है कि वह राज्य सरकार की वित्तीय सहायता के बिना उक्त ऋण का भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा। यदि राज्य को निगम की आर्थिक मदद करनी है, तो वह कर्मचारियों को वेतन देने में ऐसा कर सकता

है। इसके अलावा, निगम केवल सीमित श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में वित्तीय घाटे की दलील नहीं दे सकता। जहां तक अन्य कर्मचारियों का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता कि वह आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन केवल याचिकाकर्ताओं के संबंध में, वित्तीय बाधाएं हैं।

23. ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, हम लेटर्स पेटेंट अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज करते हैं, इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हैं, भले ही आधार विद्वान एकल न्यायाधीश से अलग हों। संबंधित सिविल रिट याचिकाओं की अनुमति है। चाहे लेटर्स पेटेंट अपील हो या रिट याचिकाएं, पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
बिलासपुर,यमुनानगर